भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2695

मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

तेलंगाना में पीएमएसजीएमबीवाई के तहत आदर्श सौर ग्राम का विकास

2695 डॉ. के. लक्ष्मण:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के तहत आदर्श सौर ग्राम के चयन हेतु क्या मापदंड अपनाए गए हैं और तेलंगाना सहित पूरे देश में इनके कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस पहल के तहत तेलंगाना में किसी गाँव को चिह्नित या चयनित किया गया है तथा रूफटॉप सौर ऊर्जा अभिग्रहण और संबंधित अवसंरचना के लिए क्या सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि आदर्श सौर ग्राम पहल ग्रामीण आजीविका, स्वच्छ ऊर्जा अभिग्रहण और संधारणीय विकास में योगदान दे?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के एक घटक के अंतर्गत हर जिले में एक मॉडल सोलर गांव (MSV) विकसित करना शामिल है, जिसमें प्रत्येक गांव के लिए 1 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता (CFA) प्राप्त हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने मॉडल सोलर गांव (एमएसवी) के चयन के लिए मानदंड और पैरामीटर प्रदान करते हुए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मॉडल सौर गांव हेतु पात्र होने के लिए, गांव को ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए तथा निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

i. नवीनतम प्रकाशित जनगणना के अनुसार, यह गांव 5,000 से अधिक आबादी वाला एक राजस्व गांव होना चाहिए।

ii. विशेष श्रेणी के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्य, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा

लक्षद्वीप के मामले में नवीनतम प्रकाशित जनगणना के अनुसार 2,000 से अधिक की आबादी वाले राजस्व गांव पात्र होंगे।

iii. जिन जिलों में 10 से कम गांव उपरोक्त जनसंख्या मानदंडों को पूरा करते हैं, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) मॉडल सोलर गांव पहल के प्रतिस्पर्धी मोड के तहत विचार किए जाने हेतु जिले के 10 सबसे अधिक आबादी वाले गांवों का चयन कर सकती है।

iv. जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) मॉडल सोलर गांव पहल के दायरे को एक मॉडल सौर पंचायत तक बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) ने सूचना दी है कि देश भर के 477 जिलों के लिए एमएसवी घोषित किए गए हैं, जिसमें तेलंगाना राज्य के 30 जिले भी शामिल हैं।

राज्य में एमएसवी के विकास के लिए तेलंगाना के एसआईए द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर, एमएनआरई द्वारा प्रत्येक गांव के लिए 1 करोड़ रुपये के सीएफए के साथ सात घोषित गांवों के लिए डीपीआर स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें रूफटॉप सौर को अपनाने और संबंधित अवसंरचना में सहायता देना और सामुदायिक स्तर पर आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है।

पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में आरईसी लिमिटेड के साथ मिलकर तेलंगाना की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) ज़िला और गाँव के स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है जिनका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और एमएसवी पहल के माध्यम से ग्रामीण आजीविका, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और सतत विकास में योगदान को सुनिश्चित करना है।

*****